National Journal of Multidisciplinary ResearchAnd Development
www.newresearchjournal.com
ISSN: 2455-9040
Received: 15-03-2025, Accepted: 15-04-2025, Published: 30-04-2025
Volume 10, Issue 2, 2025, Page No. 24-27

उत्तर प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. दिग्विजय सिंह[1], सुजाता यादव[2]
[1] एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, हंडिया पी. जी. कॉलेज, हंडिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत
[2] शोध छात्रा, शिक्षाशास्त्र विभाग, हंडिया पी. जी. कॉलेज, हंडिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
उत्तर प्रदेश के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) की स्थिति में सुधार और इनकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार और संभावनाएँ देखी जा सकती हैं। सबसे पहले, इन संस्थानों में संसाधनों की कमी को दूर करना अनिवार्य है। इसके तहत उच्च गुणवत्ता वाली लाइब्रेरी, आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण और डिजिटल शिक्षा के लिए तकनीकी साधनों का प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रशिक्षकों की गुणवत्ता और उनकी शैक्षिक दक्षता को बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही, डायट संस्थानों में प्रशिक्षकों और शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और मेरिट–आधारित बनाना अत्यंत आवश्यक है।
शोध के अनुसार, डायट संस्थानों में प्रशासनिक ढाँचे को सुदृढ़ करना और जवाबदेही बढ़ाना एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षकों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू की जानी चाहिए। इसके अलावा, इन संस्थानों को स्थानीय स्तर पर शिक्षा की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम डिजाइन करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। डिजिटल शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को शामिल करना, न केवल प्रशिक्षुओं को बेहतर अवसर प्रदान करेगा बल्कि शिक्षा के स्तर को भी सुधारने में सहायक होगा।
सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को समझने और उसमें समावेशिता लाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अद्यतन करना आवश्यक है। साथ ही, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को समुदाय के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और उनकी शिक्षा संबंधी समस्याओं को समझने पर जोर देना चाहिए। शोध में यह भी पाया गया कि इन संस्थानों की भूमिका को केवल प्रशिक्षण तक सीमित न रखते हुए, शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान का केंद्र बनाने पर भी बल देना चाहिए।
इस प्रकार, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में सुधार के लिए मजबूत नेतृत्व, पर्याप्त वित्तीय संसाधन और नवीन तकनीकी उपायों का समावेश करके इन्हें राज्य की शिक्षा प्रणाली का आधार बनाया जा सकता है। यह न केवल प्रशिक्षकों और शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर शैक्षिक अनुभव भी सुनिश्चित करेगा।

मूल शब्दः उत्तर प्रदेश, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, स्थिति, विश्लेषणात्मक अध्ययन इत्यादि

उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। यह संस्थान राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से संचालित होते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का मुख्य लक्ष्य है कि वे प्रत्येक जिले के शैक्षिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करें और चलाएं। उत्तर प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की वर्तमान स्थिति में कई सुधार और विकास कार्य किए जा रहे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना और शिक्षकों का प्रशिक्षण देना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदलने की योजना बनाई है। इसके तहत 103 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम, ऑडियो–वीजुअल उपकरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी और सौर ऊर्जा जैसे आधुनिक सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। साथ ही 50 छात्रों और 100 छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं इन सुधारों के बावजूद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे सीमित संसाधन और शिक्षकों की कमी। लेकिन इन सुधार योजनाओं से भविष्य में इन संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है, जिससे शिक्षक प्रशिक्षण को बेहतर बनाया जा सकेगा।

आवश्यकता एवं महत्व – उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा राज्य, शिक्षा क्षेत्र में तेजी से सुधार करने की दिशा में अग्रसर है। परंतु शिक्षा की गुणवत्ता में अभी भी कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिनमें प्रमुख भूमिका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की है। इन संस्थानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य–प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारना, शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा पद्धतियों से प्रशिक्षित करना और शैक्षिक नवाचार को बढ़ावा देना है।
उत्तर प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये संस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की रीढ़ माने जाते हैं। इन संस्थानों की गुणवत्ता, संसाधनों की उपलब्धता, प्रशिक्षकों की दक्षता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता सीधे तौर पर शिक्षकों की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को प्रभावित करती है। विश्लेषणात्मक अध्ययन से न केवल इन संस्थानों की वर्तमान दशा और चुनौतियों का स्पष्ट चित्र सामने आता है, बल्कि इससे शिक्षा नीति निर्माताओं को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए ठोस आधार भी प्राप्त होता है। इसके माध्यम से संसाधनों के समुचित वितरण, प्रशिक्षण पद्धतियों के नवाचार तथा प्रशासनिक दक्षता में सुधार की संभावनाओं की पहचान की जा सकती है। अतः इस प्रकार का अध्ययन उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हो सकता है।

सम्बंधित साहित्य का पुनरावलोकन– सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान–कोषों, पत्र–पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध–प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से

अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।
किसी भी विषय के विकास में किसी विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिए शोधकर्ता को पूर्व सिद्धान्तों एवं शोधों से भली–भाँति अवगत होना चाहिए। इस जानकारी को निश्चित करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध प्रारूप की प्रारम्भिक अवस्था में इसके सैद्धान्तिक एवं शोधित साहित्य की समीक्षा करनी होती है।

सम्बंधित साहित्य
यादव एवं सिंह (2004) द्वारा "शिक्षक शिक्षा एवं देश के विकास" पर अध्ययन किया गया। इसमें उन्होंने डायट पर अध्ययन किया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य डायट द्वारा संचालित सेवापूर्ण व सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का अध्ययन करना था। इस अध्ययन का एक वृहद् अवधारणा के रूप में डायट का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के क्रियाकलाप जिला स्तर के प्राथमिक शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे थे।
भारतभूषण (2004) द्वारा "सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण का एक परिदृश्य" प्रस्तुत किया गया। इन्होंने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर कार्य किया है और यह स्पष्ट किया है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सेवाकालीन प्रशिक्षण के प्रति सजग है एवं इस प्रशिक्षण को सोद्देश्य बना रहे हैं।
डॉ0 पाण्डा (2005) ने डायट के सम्बन्ध में सेवापूर्व प्रशिक्षण, डायट का आकार, प्रशासनिक प्रबन्धन, आर्थिक स्रोत व शैक्षणिक सम्भावनाओं के विषय में अध्ययन किया। इस प्रकार उन्होंने डायट के अन्दर तथा बाहर जोड़ने के लिए कार्यक्रम नियमन की विधि का भी अध्ययन किया। डॉ० पाण्डा ने 6 डायट आन्ध्र प्रदेश से तथा उतने ही डायट राजस्थान से चयनित किया। डायट में शिक्षा कार्यक्रम के लिए सेवारत अध्यापकों का योजना एवं प्रबन्धन के लिए सक्रिय ढाँचे को प्रस्तुत किया। उन्होंने अध्ययन में पाया कि अभी तक बहुत सारे डायटों में स्वयं का निर्मित भवन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। डायट राजस्थान की तुलना में डायट आंध्र प्रदेश में स्वतंत्र रूप से कर्मचारी उपलब्ध करा लिया है। उनको जो धनराशि निर्गत की गई थी, उनमें आन्ध्र प्रदेश के डायट द्वारा धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है जबकि राजस्थान को भी समान धनराशि उपलब्ध करायी गई थी परन्तु उस राशि को खर्च करने के बारे में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।
पंकाजम (2007) द्वारा तमिलनाडु के "जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों" का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में 1987–88 के बीच डायट के विकास का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य डायट के द्वारा कराये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना और डायट के और प्रभावशाली बनाने के उपायों का सुझाव देना था। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुए कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति ठीक थी। सभी संस्थानों के पास अपने मॉडल स्कूल थे। सभी डायट में भौतिक तथा मानवीय संसाधनों की स्थिति ठीक थी। डायटों के प्रयोगशाला एवं उपकरणों की स्थिति अच्छी नहीं थी।

शोध अध्ययन के उद्देश्य – इस शोध के उद्देश्य निम्नवत हैं –
उत्तर प्रदेश के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को भौतिक तथा मानव संसाधनों के सन्दर्भ में अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएं– प्रस्तुत शोध की परिकल्पना अधोलिखित है –
उत्तर प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की भौतिक स्थिति क्या है?

शोध विधि – प्रस्तुत शोध में विवरणात्मक अनुसन्धान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या – प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य ,वरिष्ठ प्रवक्ताओं/प्रवक्ताओं तथा प्रशिक्षणार्थियों को जनसंख्या के रूप में चुना गया है।

न्यादर्श– प्रस्तुत शोध में शोधकत्री ने सम्भाव्य विधि के अंतर्गत आने वाले सरल यादृच्छिक न्यादर्शन (पउचसम तंदकंवउ उचसपदह) विधि का प्रयोग किया है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में से प्रत्येक मंडल से 2 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत 36 प्राचार्य, 90 वरिष्ठ प्रवक्ताओं/प्रवक्ताओं तथा 360 प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है।

शोध उपकरण– प्रस्तुत शोध में शोधकत्री द्वारा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए स्वनिर्मित अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

शोध से प्राप्त परिणामों का सारणीबद्ध व उनकी व्याख्या अग्रवत है–
परिकल्पना– 1 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति एवं समस्याएँ (प्राचार्य /प्रवक्ताओं) की प्रतिक्रिया–

संस्थान की अवस्थिति और संरचना
आपके DIET में पर्याप्त भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं।

प्राचार्य/प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
हाँ	98	90.74:
नहीं	10	09.26:

DIET (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) में पर्याप्त भौतिक संसाधनों की उपलब्धता पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 90.74: प्राचार्य और प्रवक्ताओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जो इस बात का संकेत देता है कि संस्थान में शैक्षणिक और प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए आवश्यक भौतिक संसाधन समुचित रूप से उपलब्ध हैं। यह संस्थान की प्रभावी कार्यप्रणाली और प्रशासन की क्षमता को दर्शाता है। हालांकि, 09.26: प्राचार्य और प्रवक्ताओं द्वारा नकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ क्षेत्रों में संसाधनों की कमी या उनकी गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। निष्कर्षतः, अधिकांश प्राचार्य और प्रवक्ताओं ने DIET में भौतिक संसाधनों की स्थिति को संतोषजनक माना है, लेकिन कुछ सुधार की संभावनाएं बनी हुई हैं।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के छात्राध्यापकों की प्रतिक्रिया–

संस्थान की भौतिक स्थिति–
संस्थान में पर्याप्त कक्षाओं की व्यवस्था है।

छात्राध्यापकों की प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
हाँ	280	77.78:
नहीं	80	22.22:

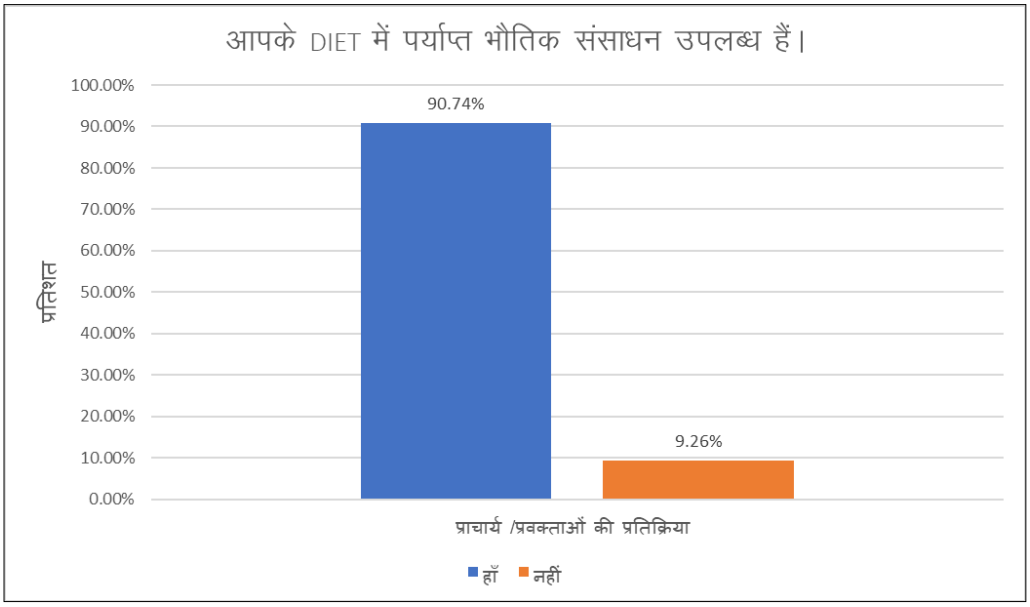

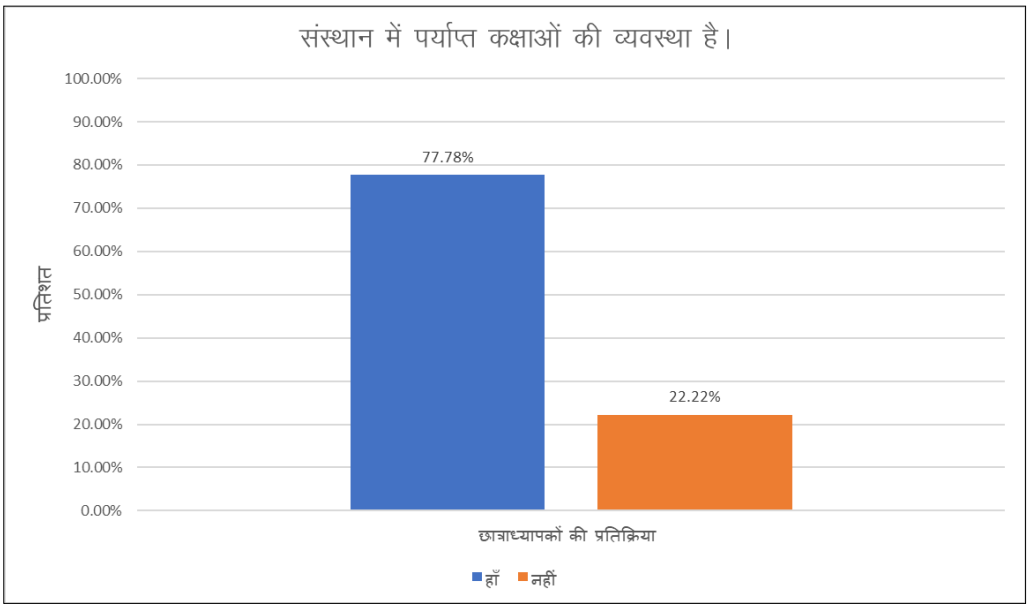

संस्थान में कक्षाओं की पर्याप्त व्यवस्था के संबंध में अधिकांश छात्राध्यापकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, जैसा कि सर्वेक्षण के परिणामों से स्पष्ट है। 77.78: छात्राध्यापकों ने इस व्यवस्था को संतोषजनक माना है, जो संस्थान की अच्छी कक्षागत सुविधाओं को दर्शाता है। हालांकि, 22.22: छात्राध्यापकों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जो यह संकेत करता है कि कुछ छात्राध्यापकों को कक्षाओं की संख्या या उनकी उपलब्धता में कोई समस्या हो सकती है। इस संदर्भ में सुधार की आवश्यकता है, ताकि सभी छात्राध्यापकों को समुचित सुविधाएं मिल सकें और उनका अनुभव बेहतर हो सके।

निष्कर्ष – उत्तर प्रदेश के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सुधार और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संस्थानों की अवस्थिति और संरचना को लेकर किए गए शोध में यह निष्कर्ष निकलता है कि डायट संस्थान जिले स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, और शैक्षिक नवाचारों के लिए एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इन संस्थानों का भौतिक ढांचा, प्रशासनिक व्यवस्था और संसाधनों की उपलब्धता का स्तर जिले की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

शोध में पाया गया है कि अधिकांश डायट संस्थानों में भवन और बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं है, जिससे प्रशिक्षण गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित करने में कठिनाई होती है। प्रशिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या भी कई संस्थानों में मानक से कम पाई गई, जिससे प्रशिक्षण गुणवत्ता प्रभावित होती है। हालांकि, कुछ डायट संस्थानों में आधुनिक उपकरण, तकनीकी संसाधन, और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं।

संरचनात्मक दृष्टि से, डायट संस्थानों का प्रशासनिक ढांचा राज्य स्तर पर डायट प्राचार्य के अधीन होता है, जिनके पास शैक्षिक गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय आवश्यकताओं और भाषा को शामिल करने की पहल की गई है। हालांकि, शोध से यह भी स्पष्ट हुआ है कि बजट आवंटन, सामुदायिक भागीदारी और प्रशिक्षकों के लिए नियमित कौशल विकास कार्यक्रमों की कमी के कारण कई क्षेत्रों में यह संस्थान अपने लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर पा रहे हैं।

कुल मिलाकर, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की अवस्थिति और संरचना में सुधार के लिए आवश्यक है कि सरकार और स्थानीय प्रशासन इनकी चुनौतियों को पहचाने और पर्याप्त वित्तीय व संरचनात्मक समर्थन प्रदान करें। इन संस्थानों की प्रभावशीलता

को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षकों की क्षमता निर्माण, तकनीकी संसाधनों का विस्तार और आधुनिक शिक्षण तकनीकों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) की भौतिक स्थिति पर किए गए शोध में छात्राध्यापकों ने पाया कि इन संस्थानों की भौतिक स्थिति में कई सुधार की आवश्यकता है। शोध निष्कर्ष के अनुसार, कई डायट संस्थानों में बुनियादी ढांचे की कमी स्पष्ट रूप से देखी गई। इनमें पर्याप्त कक्षाओं, बैठने की सुविधाओं, स्वच्छ पेयजल, शौचालयों और पुस्तकालयों का अभाव शामिल है। कुछ संस्थानों में लैबोरेटरी और तकनीकी उपकरण उपलब्ध तो हैं, लेकिन वे पुराने या खराब स्थिति में हैं, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, खेल–कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए समुचित मैदान या सुविधाएं भी अधिकांश संस्थानों में उपलब्ध नहीं हैं। छात्राध्यापकों ने यह भी रेखांकित किया कि कई डायट संस्थानों में पर्याप्त शिक्षण सामग्री और डिजिटल संसाधनों की कमी है, जो वर्तमान शिक्षा के तकनीकी युग में बड़ी चुनौती है। हालांकि, कुछ संस्थानों में सुधार की पहल की जा रही है, लेकिन उसकी गति धीमी है। कुल मिलाकर, शोध से यह निष्कर्ष निकाला गया कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए भौतिक संसाधनों में पर्याप्त निवेश और उनके रखरखाव की सख्त आवश्यकता है।

शोध की उपयोगिता – शिक्षा किसी भी समाज के विकास का मूल आधार है और शिक्षक उसके निर्माण का महत्वपूर्ण स्तंभ। भारत जैसे विकासशील देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, शिक्षकों के प्रशिक्षण का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) ऐसे संस्थान हैं जो शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। इन संस्थानों की स्थिति का विश्लेषण करके, उनकी उपयोगिता को समझना और उनका विकास करना अत्यावश्यक है। यह शोध इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (2020): शिक्षक शिक्षा की वर्तमान स्थिति, एनसीईआरटी, नई दिल्ली।
2. उत्तर प्रदेश सरकार (2021): जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की वार्षिक रिपोर्ट, शिक्षा विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. सिंह, आर. (2019): भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक प्रशिक्षण की भूमिका, ज्ञान भारती प्रकाशन, वाराणसी।
4. मिश्रा, एस. (2020): उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा की चुनौतियाँ, भारतीय शैक्षिक समीक्षा, 45(3), 112–120।
5. शुक्ला, पी. (2018): DIET संस्थानों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, विश्वविद्यालय प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. शर्मा, ए. (2022): शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षण गुणवत्ता, शिक्षा विमर्श, 39(2), 88–95।
7. बर्मन, डी. (2021): शिक्षा में नवाचार और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय शैक्षिक अध्ययन संस्थान, भोपाल।
8. तिवारी, एम. (2017): उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में DIET की भूमिका, शिक्षा संवाद, 33(1), 55–63।
9. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2019): राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा नीति दस्तावेज, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. पांडेय, वी. (2023): प्रशिक्षण संस्थानों में संसाधनों की स्थिति: एक क्षेत्रीय अध्ययन, आधुनिक शिक्षा, 50(4), 101–110।